खबर (दार) झरोखा

विकास नारायण राय

राजमार्ग पर है जान गँवानी तो साइबर मार्ग पर पड़ेगी जेब कटानी

सड़क और साइबर, विकास के मान्य पैमाने हैं। ये ही, फ़रीदाबाद जैसे तमाम शहरों के वासियों के लिए विनाश के रास्ते सिद्ध हो रहे हैं। सड़कें आपको गंतव्य पर पहुँचाने के लिए बनाई गयी हैं न कि अस्पताल या स्वर्ग भेजने के लिए। इसी तरह साइबर दुनिया आपको काम में सुविधा पहुँचाने के लिए निर्मित की गयी न कि ठगी का शिकार बनने के लिए। लेकिन किसी भी पल आप सड़क दुर्घटना या साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं।

अंधाधुंध सड़क निर्माण को विकास का पर्यायवाची बनाने के क्रम में, आम आदमी की सुरक्षा और सुविधा ताक पर रख दी जाती है। उनके रख-रखाव के बेपरवाह और भ्रष्ट तरीकों में जानलेवा दुर्घटनाओं के बीज पनपने दिए जाते हैं, बेशक आप स्वयं इन सड़कों पर कितनी ही सावधानी क्यों न अपनायें। इसी तरह, डिजिटल इंडिया के शोर शराबे के बीच साइबर ठगों की किसी को भी बे बुलाये मेहमान की तरह घेर सकने को क्षमता और पहुँच बेहद बढ़ गयी है। घर में अकेलेपन की मारी कोई गृहिणी हो, पार्क में समय गुजारता पेंशनर या रोजगार के लिए मगजमारी करता युवा सब उनके निशाने पर होते हैं।

यूँ तो मोदी सरकार ने फ़रीदाबाद को स्मार्ट सिटी की विशिष्ट लिस्ट में शामिल कर रखा है लेकिन लगता है जैसे इस महानगर की अपराध शाला में सिर्फ कानून तोड़ने वाले ही स्मार्ट हुये हैं, उन्हें पकड़ने वाली पुलिस नहीं। राजमार्ग तो, ट्रैफिक पुलिस के तामझाम के बावजूद, बेहद जान-लेवा सिद्ध हुये हैं ही, साइबर मार्ग के रास्ते पर भी, नए-नए किस्म के अपराधों की बेकाबू बाढ़ आ गयी। लगती है। पुलिस के दावे जरूर हैं चुस्त-दुरुस्त साइबर सेल के या चौकस ट्रैफिक अभियान के, पर बस जब-तब खास मौकों पर अपना ढोल पीटने के अंदाज वाले ही। दरअसल, पुलिस लाख मत्था मारे तो भी अपर्याप्त संख्या और कमजोर प्रशिक्षण के चलते उनके लिए यह एक असंभव काम ही होगा।

लिहाजा, अपराध के इन दोनों रास्तों पर पुलिस का ढर्रा, रेत में शतुरमुर्ग की गर्दन की तरह, समस्या से आँख मूंदने वाला रहा है. किसी भी सड़क पर दस मिनट खड़े हो जाइए और आपको जान जोखिम में डालने की वजह और उसका सही निदान दोनों दिख जायेंगे। त्रुटिपूर्ण सड़क इंजीनियरिंग, कारों की अनियंत्रित गति, भारी वाहनों की यांत्रिक कमियां, शराबी ड्राइवर, पैदल और दो पहिया वाहन के चलने या सड़क पार करने की सुविधाओं का अभाव! जबकि पुलिस व्यस्त दिखेगी विशिष्ट व्यक्तियों के लिए रास्ते खुलवाने या ट्रैफिक चेकिंग की रूटीन खाना-पूर्ति करने में।

इसी तरह, रोज ही कंप्यूटर, बैंक खातों, एटीएम, क्रेडिट कार्ड या फोन पर कोई न कोई साइबर गैंग अपने संभावित शिकारों का पीछा करता मिल जायेगा। छिपकर नहीं, चौड़े में और अधिकांशत: प्रचारित कर। ऐसे में क्या यह सवाल पूछना जायज नहीं बनता कि आखिर हमारी पुलिस को अपराध के ये साक्षात आयाम नजर क्यों नहीं आते? क्या पुलिस वाले इसी दुनिया में नहीं रहते? वे पीड़ितों की अपने पास आने प्रतीक्षा में क्यों बैठे रहते हैं? क्या संभावित सड़क दुर्घटनाओं और पकते साइबर अपराधों की रोकथाम उनका काम नहीं? जबकि दोनों मामलों में पहल कर पाना उनके लिये संभव है।

एक जमाना था बातों के जाल में फंसा कर निवेश, दान, मदद, लाटरी, विवाह, पुरस्कार, इत्यादि के झांसे से ठगी करने वाला हर साइबर गैंग झारखण्ड से धंधा संचालित करता था। आज ऐन दिल्ली के उत्तम नगर में उनके हब खुले हुये हैं। ये गिरोह किसानों और मजदूरों को लालच देकर उनके आधार कार्डों से लिंक बैंक खाते दिल्ली में या आस पास फ़रीदाबाद जैसे शहरों में खुलवाते हैं। इन खातों में ठगी की रकम फंसे शिकारों से एक मुश्त या किश्तों में डलवाई जाती है। और जब तक पुलिस हरकत में आती है, रकम निकाली जा चुकी होती है और गिरोह छू मंतर हो चुका होता है। आगे बढ़कर इन अपराधों की रोकथाम, पुलिस की सोच या कार्य पद्धति का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा? मानो जो अपराध साक्षात सामने घट रहा है या जिसकी पूरी तैयारी है वह देखना पुलिस के लिए जरूरी ही नहीं। पुलिस वाला अपने थाने, चौकी, सेल, ऑफिस में बैठा रहता है जब तक कि ठगी का मारा उसके या रसूखदारों के चक्कर न काटना शुरू कर दे। साइबर अपराधों के भुक्त भोगियों का अनुभव है कि इन मामलों में पुलिस आपको जब तक चाहे चक्कर कटाती रह सकती है।

पुलिस विभाग की प्रथा अनुसार उनके द्वारा दर्ज किये गए अपराधों की ही सहेज होती है। कभी-कभी, जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो अपराध दर्ज न करने पर उनकी जवाब तलबी हो जाना भी मुमकिन है। लेकिन, पुलिस की अपनी नियमावली के अनुसार, संभावित अपराधों की रोकथाम में भी पुलिस की जवाबदेही होनी चाहिए। हालाँकि शायद ही कभी ऐसा होता हो। इस कलेवर में पुलिस प्राय: या तो राजनीतिक आकाओं के लिए बंदोबस्त में लगी दिखेगी या सड़कों पर वाहन चालकों को ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर तंग करने में या फिर शासन-प्रशासन के विरोध में इकट्ठा हुए लोगों से निपटने में। जब फरीदाबाद स्मार्ट सिटी घोषित नहीं हुआ था, तब भी ऐसा ही हाल था और अब जब स्मार्ट सिटी घोषित हो गया है, तब भी यही हाल है। जब फरीदाबाद में पुलिस का नेतृत्व एक एसपी रैंक के अफसर के हाथ में था और अब जब एक आईजी रैंक के पुलिस कमिश्नर के हाथ में है, हाल वही है। एक ओर पुलिस की कागजी आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है जबकि दूसरी ओर जमीनी सच्चाई है कि इस महानगर में लोग शनि देवता के भरोसे ही सड़क यात्रा पर निकलते हैं। साइबर दुनिया का इस्तेमाल करने वाले तो ठगों के रहमो-करम पर ही जीने को मजबूर हैं। आप साइबर माध्यम से पुलिस को अपने लुटने की शिकायत भेजिए, आपको कभी जवाब नहीं मिलेगा।

स्वयं फ़रीदाबाद पुलिस के अपने आंकड़ों के मुताबिक, रोजाना गंभीर सड़क हादसे और गंभीर साइबर ठगी के मामले उनके पास दर्ज हो रहे हैं। यकीन जानिए, कई गुणा ज्यादा ऐसे अपराध पुलिस दर्ज ही नहीं करती। यह भी आपकी किस्मत है कि आप इस 'दर्ज' या 'प्रतीक्षा' सूची में अभी शामिल नहीं हुए हैं। दरअसल, हर वह व्यक्ति जो सड़क या साइबर का इस्तेमाल कर रहा है, इन अपराधों का संभावित शिकार भी कहा जा सकता है। कौन नहीं जानता यह तथ्य, सिवाय हमारी पुलिस के! या, आज के सड़क पुरुष नितिन गडकरी और साइबर पुरुष नरेंद्र मोदी के ?

सरकारी बैंकों में पैसा नहीं, सरकार का झूठ जमा है

रविश कुमार

मुद्रा लोन के बारे में सच्चाई बताऊँगा तो आप भी चौंक जायेंगे। बहुत सारे बैंको में 3महीने के क्लोजिंग पर उन एकाउंट पर जयादा ध्यान होता है जो एनपीए होने के कगार पर होते हैं। अब मैनेजर एक 40 हजार या 50 हजार का मुद्रा लोन बेनामी नाम पर करता है,उस रुपये से वो 5-6 लोन सही कर लेता है जो एनपीए होने वाले होते हैं। क्योंकि इससे ऊपर से वो गाली खाने से बच जाता है। अब इस मुद्रा लोन के ब्याज देने के लिए अब अगले क्वाटर में जो बेनामी मुद्रा लोन करेगा,उससे चुका देगा। देखिए सिर्फ ऊपर से दिए टारगेट पूरा हो जाये,कोई गाली सुनना न पड़े उसके लिए हमको कितनी हेराफेरी करनी पड़ती है कैसे हमें रात में नींद आती है हम ही जानते हैं। मैं शराब पीने लगा हूं

यह कथा एक बैंकर की आत्मकथा है। अनगितन बैंकरों ने अपने नैतिक संकट के बारे में लिखा है। वे अपने ज़मीर पर झूठ का यह बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुद्रा लोन लेने वाला नहीं है मगर बैंकर पर दबाव डाला जा रहा है कि बिना जांच पड़ताल के ही किसी को भी लोन दे दो। मैं दावा नहीं कर रहा मगर बैंकरों के ज़मीर की आवाज़ के ज़रिए जो बात बाहर आ रही है, उसे भी सुना जाना चाहिए।

मैंने बैंकरों के हज़ारों मेसेज पढ़े हैं और डिलिट किए हैं। अब लग रहा है कि इनकी बातों को किसी न किसी रूप में पेश करते रहना चाहिए। आपको लग सकता है कि एक ही बात है सबमें मगर झूठ का बोझ इतना भारी हो चुका है कि हर दिन एक नया किस्सा हमें चौंका देता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक बैंकर ने हमें क्या लिखा है।

रविश जी, मैं आपको पहले भी एक बार मैसेज कर चुका हूँ। मेरी कुछ महीने की नौकरी शेष है। रिटायर होने जा रहा हूं। पिछले कुछ बरसों में मेरे स्वयं के मन से अपने संस्थान की प्रतिष्ठा कम हो गई है और कोई वजह नहीं बची है कि मैं उस पर गर्व कर सकूँ। हमारी शाखाओं में प्रतिदिन कई ग्राहक आते हैं जो कहते हैं कि उन्हें लेनदेन के मैसेज नहीं मिल रहे हैं(तकरीबन तीन साल से यह कमी है) हम लोग इस पर तरह तरह केबहाने बनाते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को ह्यद्वह्य सेवा के लिए प्रति तिमाही 15 रु + जीएसटी लेती है (यानी सरकार तक भी हिस्सा जाता है) उस सेवा के लिए जो प्रॉपर तरीके से दी ही नहीं जाती है। मुश्किल से 20-30 प्रतिशत लेनदेन की सूचना जाती होगी पर चार्जर्स बेशर्मी से पूरे लिए जाते हैं। आप शाखाओं में जाकर ग्राहकों से स्वयं पूछें तो आपको हकीकत पता चलेगी। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक ग्राहक को बैंक पिछले 2 साल में काटे पैसे वापस करे और इस तरह से अपनी कुंडली में कुछ सुधार करे। क्या इसके लिए कुछ ग्राहक अदालत के सब ग्राहकों को उनका पैसा लौटवा सकेंगे? इस अन्याय के विरुद्ध मैं आपको साथ देखना चाहता हूँ।

बैंक सीरीज से फर्क यही आया है कि बैंकरों की आत्मा मुखर हो रही है। वे भी इंसान हैं। वे अपने ज़मीर पर बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्हें पता है एक दिन चेयरमैन और ऊपर के लोग हवा में उड़ जाएंगे और ये लोग जेल जाएंगे। अब यह झूठ इतना फैल चुका है कि रिज़र्व बैंक भी बेअसर हो चुका है। उसकी क्षमता नहीं है कि वह इस पैमाने पर फैले झूठ को पकड़ सके। अगर आज बैंकरों को यक़ीन हो जाए कि हर हाल में जनता उनका साथ देगी तो वे ऐसे ऐसे झूठ सामने रखने लगेंगे जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। आपके पैसे तो उड़ ही चुके हैं।

अंग्रेज़ी में एक मैसेज आया है, जनाब यही कह रहे हैं कि सबको ऊपर से ठीक लगे इसलिए बैंकों के बहीखाता में फर्ज़ी जोड़-घटाव किया जा रहा है। परम पूजनीय नीरव मोदी जी तो खुद भाग गए, वित्त मंत्री अभी तक नहीं बोल पाए मगर इसकी सज़ा बैंकरों को मिल रही है।

इस राज्य से उस राज्य में तबादला करके। तबादले का जो खर्च आता है वो भी अब बैंक पूरा नहीं देता है। आप अगर दो हज़ार बैंकरों से बात कर लेंगे तो यही लगेगा कि बैंकर भी अपनी जेब से बैंक चला रहे हैं। जिसका ज़िक्र में गुलाम बैंकरों की दास्तान में कर चुका हूं। वे अपनी गुलामी को समझने लगे हैं। अपनी नौकरी दांव पर रखकर सीधे बैंक के खिलाफ़ तो नहीं खड़े हो सकते मगर अब उनका ज़मीर बोलने के लिए मजबूर करने लगा है। देश भर के उन जगहों से बैंकर मुझे अपनी व्यथा बता रहे हैं जहां मेरा चैनल कई महीनों से आता भी नहीं है। सरकार के दावों को बड़ा और सच्चा बनाने के लिए बैंकों के भीतर जो फ़र्ज़ीवाडा हो रहा है, उस पर आप आज भले न ध्यान दें मगर जिस दिन ये बैंक भरभराएंगे, सड़क पर आकर आप रोते रह जाएंगे।

मैं रोज़ सोचता हूं कि इन मैसेज का इस्तमाल कैसे करूं। अब लगता है कि डिलिट करने से पहले उनकी बातों का एक हिस्सा उठाकर यहां रख दूं। मुद्रा लोन को लेकर जो फर्ज़ीवाड़ा चल रहा है, जो किस्से मैंने पढ़े हैं, मैं अब समझने लगा हूं कि अमरीका और ब्रिटेन के बैंकों के भीतर जो हुआ था, वही अब हिन्दुस्तान में हो रहा है। बैंकर अभी भी इस संकट को नहीं समझ रहे हैं। वे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं सैलरी के लिए मगर व्यथा बताते हैं क्रास सेलिंग और झूठ बोलकर बीमा बेचने के दबाव की। मुद्रा लोन का आंकड़ा बड़ा लगे उसके लिए किए जा रहे फर्ज़ीवाड़े के कारण वे टूट रहे हैं। बैंक के ढांचे में किसी राज्य में चोटी के दस पांच लोग ही होते हैं। इनके ज़रिए हज़ारों कर्मचारियों और अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है। बीमा बेचने का कमीशन इन्हीं दस पांच चोटी के अफसरों को मिलता है। जितना मैंने समझा है।

"Sir, bank has also sold me insurance policy with home loan forcefully without my consent and when I requested them to cancel in freelook period, they have not done the same...." अंग्रेज़ी में लिखे इस मेसेज से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि बिना इनकी अनुमति के बीमा पालिसी बेच दी गई। जब अंग्रेज़ी वाले बैंकों के झूठ के शिकार हैं तो कल्पना कीजिए ग़रीबों के साथ क्या हो रहा होगा। मुझे यह भी सुनने को मिला है कि ग़रीब खातेधारों के खाते से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, बिना उनकी अनुमति के। जब वे वापस करने की मांग कर रहे हैं तो बैंकर ने बताया कि पैसा वापस करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं। एक बैंक के मैनेजर ने बताया कि इस तरह हमारा ही बैंक पांच छह हज़ार करोड़ का मुनाफा बना लेता है। अटल पेंशन योजना। अटल जी के नाम से भी लोगों के साथ धोखा किया जा सकता है, मुझे यकीन नहीं था। सैंकड़ों की संख्या में बैंकर बता रहे हैं कि कोई ले नहीं रहा, हमें देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक बैंकर ने लिखा कि आज जब सात बज गया तो बाहर गया। चाय की दुकान से तीन लोगों को पकड़ लाया। दस्तखत कराया और अपनी जेब से सौ सौ सो रुपये डालकर अपना टार्गेट पूरा किया और घर चला गया। वरना साढ़े नौ बजे रात तक बैठना पड़ता। इस तरह से अटल पेंशन योजना बेची जा रही है। कई बैंकरों ने कहा कि ऐसे भी यह योजना सही नहीं है। इसमें कोई दम नहीं है। हमने पूछा हमें इतनी बारीकी समझ नहीं आती तो उनका ये जवाब है।

सर, आज के ज़माने में किसी ग्राहक को इंवेस्टमेंट के बारे में बताओ तो उसका पहला सवाल होता है कि रिटर्न कितना है और कितने साल में। सर, अटल पेंशन योजना के केस में एंट्री ईयर्स है 20 साल। उसके बाद आता है ग्राहक के उम्र का फंडा जिससे प्रीमियम तय होता है। 20 साल का सुनकर ही 10 में से सात लोग गायब हो जाते हैं। जो तीन बचे वो तीन भी अच्छे संबंधों के कारण प्लान ले लेते हैं। अब आती है पालिसी चलाने की बात। मैंने अभी तक कुछ 70 अटल पेंशन योजना की है। जिनमें से शायद ही किसी में 3- 4 प्रीमियम से ज़्यादा जमा हुआ होगा। सर, मैंने एम बी ए की पढ़ाई की है। मैंने अपना सारा ज्ञान और तरीके लगा दिए कि ग्राहक को सब कुछ बता कर इसे बेच लूं, मगर कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा होता तो मैं खुद नहीं ले लेता। अच्छा नहीं लगता है अपनी नौकरी बचाने के लिए, झूठी शान से अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, एक ग्राहक जो भरोसे से अपनी मेहनत की कमाई मेरे भरोसे भविष्य के लिए बचाना चाहता है, उसे ग़लत सलाह से जाया करूं। जितनी मेहनत हम बैंक वालों से बीमा बेचने के लिए करवाई जा रही है, उस टाइम में बैंकर्स बिजनेस का फीगर चेंज कर सकते थे।

महिला बैंकरों की हालत पढ़कर मेरी हालत खराब होने लगी है। शनिवार शाम जब मेरी किताब लांच हो रही थी तब एक नंबर लगातार फ्लैश कर रहा था। इतनी बार फ्लैश किया कि अंत में चिढ़ गया। मैं ही ऊंची आवाज़ में बोलने लगा कि आप मेसेज कर देते। ऐसा क्या है कि आप लगातार आधे घंटे से फोन कर रहे हैं। उधर से आती कातर आवाज़ ने मेरा पूरा मूड बदल दिया। भूल गया कि अपनी किताब के लांच में आया हूं।

सर, मेरी सहयोगी को बीमा न बेच पाने के कारण बैंक में बिठा लिया है। मैं तो आठ बजे निकल गया मगर उसे साढ़े नौ बजे रात के बाद ही छोड़ेंगे। उसका बच्चा बहुत बीमार है। बहुत तेज़ बुखार है। घर में कोई नहीं है। यहां अकेले अपने बच्चे के साथ रहती है। आप न्यूज़ फ्लैश कर देते तो उसे छुट्टी मिल जाती। वैसे भी उसे बैंक से घर आने में चालीस मिनट लगेंगे। उस मां की हालत बहुत खराब हो गई है। रोज़ की यही कहानी है। हम बीमा नहीं बेचते हैं तो बैंक में अफसरों को देर रात तक बिठा कर रखा जाता है।

" I am also a banker and I had to go too bank today with my kid , as nobody was there for take care of my son at home"

आप समझ गए होंगे कि यह मेसेज महिला बैंकर का है। रविवार को भी बैंकरों को जाना पड़ता है। उसके बदले उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती है। महिला बैंकरों की हालत पढ़कर असहाय सा महसूस करने लगा हूं। कई बार लगता है कि सरकार,चेयरमैन,ईडी टाइप के अफसरों की हेंकड़ी इतनी बढ़ सकती है या हमें इतनी बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि ये हमारी हालत गुलाम जैसी कर देंगे। मैं किसी भावावेश में नहीं कहता कि बैंकों में जाकर वहां काम कर रही महिलाओं को बचा लीजिए।

सरकार बैंकों के भीतर जो झूठ जमा कर रही है,वहां अब झूठ ही बचा है। आप को मीडिया चुनावी जीत के किस्से दिखा रहा है,मगर आदमी की हालत गुलाम सी हो गई है, वो नहीं दिखाएगा क्योंकि गोदी मीडिया तो खुद में गुलाम मीडिया है। आज न कल 13 लाख बैंकरों को सोचना पड़ेगा कि चोटी के चंद अफसरों को मिलने वाले कमीशन के लालच में क्या वे अपने लिए दासता स्वीकार कर सकते हैं? महिला बैंकरों को एक दूसरे का हाथ थामना ही होगा, निकलना ही होगा, आज़ादी के लिए कीमत चुकानी पड़ती है।

नोट- इस लेख को गांव गांव पहुंचा दें और लोगों को बता दें कि बैंकों के भीतर महिला बैंकर गुलाम की तरह रखी गईं हैं, उन्हें बचाना है। मर्द बैंकरों की भी हालत बुरी है। उन्हें भी बचाना है।